

संपादकीय

दिया तले अंधेरा... मेडिकल के हाल बेहाल रीवा

का संजय गांधी अस्पताल अब इलाज के लिए नहीं, बल्कि कारनामों के लिए जाना जा रहा है। डॉक्टरों ने एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर दिया। परिजन शव वाहन बुक करके उसे पर ले जाने लगे, तभी हाथ पकड़ा तो सांसें चल रही थीं। यह कोई मामूली चूक नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही है। यह घटना अकेली नहीं है। पिछले एक महीने में आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली उजागर करते हैं।

मंत्री जी के राज में स्वास्थ्य सेवाओं में इतनी तस्करी हुई है कि अब जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बताया जा रहा है। इंदौर के सरकारी अस्पताल में मासूम बच्चों ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप ने बच्चों की जान ले ली। किसी कंपनी ने जहर बेचा और सरकारी तंत्र उसे टॉफी समझकर बांटा रहा। यह तस्करी नहीं, व्यवस्था की भयावह विफलता है।

रीवा की घटना ने सिस्टम को नंगा कर दिया। संजय गांधी अस्पताल में जच्चा-बच्चा मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि नई घटना ने सबको हिला दिया। डॉक्टरों ने बिना पर्याप्त जांच के मरीज को मृत घोषित कर दिया। सोचिए, यदि परिजनों ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो जिंदा व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाता। यह उस शहर में हो रहा है, जिसे स्वास्थ्य मंत्री अपना गढ़ बताते हैं। गृह जिले में ही जब यह हाल है तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

इंदौर, छिंदवाड़ा से रीवा तक मौतों की एक ही कहानी दिखाई देती है – अव्यवस्था, लापरवाही और जवाबदेही का अभाव। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। बिस्तर कम गड़ रहे हैं, मरीज जमीन पर इलाज कराने को मजबूर हैं, डॉक्टरों की कमी है और दवाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद सरकारी तंत्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे करता रहता है। हर कांड के बाद जांच के आदेश, निलबन या तबादले की कार्रवाई होती है और कुछ समय बाद मामला शांत पड़ जाता है। सवाल यह है कि बड़ी जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही कब तय होगी? कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में प्रदर्शन किया और डीन-अधीक्षक के खिलाफ नारेबाजी को तो पुलिस आगे आ गई। दो घंटे तक अधीक्षक बाहर नहीं आए। कार्यकर्ताओं को अस्पताल में घुसने से रोका गया और पुलिस तथा छात्रों में झड़प भी हुई। मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियों का समाधान प्रार्थामिकता होनी चाहिए, न कि व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को दबाना।

रीवा में शव घर ले जाने के लिए शव वाहन तक नहीं मिलने की शिकायतें भी गंभीर हैं। परिजनों को निजी वाहन बुक करना पड़ता है। पैसे नहीं हों तो कंधे पर शव ढोने की मजबूरी बन जाती है। यह स्थिति किसी भी संवेदनशील व्यवस्था के लिए शर्मनाक है।

स्वास्थ्य मंत्री को अब आत्मपंचन करना चाहिए। केवल एसी कमरों में बैठक करने से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जमीन पर उतरकर अस्पतालों की वास्तविक स्थिति देखनी होगी। बिना सिफारिश इलाज करारक और मरीजों के बीच समय बिताकर ही व्यवस्था की सच्चाई समझी जा सकती है। जब जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाए, बच्चों की मौत जहरीली दवा से हो और अस्पतालों में मासूम तड़पते रहें, तो समझना होगा कि व्यवस्था गंभीर संकट में है। अब केवल जांच नहीं, ठोस जवाबदेही चाहिए और इसकी शुरुआत सबसे ऊपर से होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मंत्री के शहर में ही स्वास्थ्य व्यवस्था की अर्धी उठती दिखाई दे रही है। मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला स्वास्थ्य मंत्री हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल होगा। यह उनके गृह जिले रीवा में स्वास्थ्य विभाग की बदहाली पूरे प्रदेश के हालात बयां कर रहे है।

आजकल

फलाईओवर भ्रष्टाचार का रिसाव

राजधानी भोपाल में गणेश मंदिर से आंबेडकर तक बना फलाईओवर सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि सरकारी इंजीनियरिंग के फेल होने का स्मारक बनता दिखाई दे रहा है। द्रष्टाटन के 15 दिन के भीतर गड्डे, सर्विस रोड पर जलभराव, रिटिंगन वॉल से पानी का रिसाव और जगह-जगह दरारें सामने आ गईं। यह किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल है। हाईकोर्ट ने जब आड़े हाथों लिया तो विभाग की नौद खुली।

इस पूरे मामले को सबसे शांतिर पहलू यह है कि फलाईओवर खराब हुआ तो पीडब्ल्यूडी ने 4.69 करोड़ रुपये से मरम्मत का टेंडर करने की तैयारी कर ली। यानी गलती ठेकेदार करे और पैसा जनता का लगे। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब केंद्र के लिए पैसे नहीं हैं तो मुफ्त में होने वाले काम के लिए 4.69 करोड़ रुपये क्यों? सवाल सरकारी जेब से ज्यादा नीयत पर था। विभाग ठेकेदार की जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार क्यों था, इसका जवाब भी मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि मरम्मत और रखरखाव का पूरा खर्च ठेका कंपनी उठाएगी। 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि भी वसूली जाएगी। यानी जो काम अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को करना था, उसके लिए अदालत की फटकार जरूरी पड़ी। सवाल यह है कि यदि जंहति याचिका नहीं लगती और हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या 4.69 करोड़ रुपये सरकारी खजाने से निकल जाते? फलाईओवर का निर्माण 31 दिसंबर 2024 को पूरा हुआ था और 2026 तक ठेके की गारंटी थी। फिर इतनी जल्दी सड़क और निर्माण में खामियां कैसे आई? निर्माण के साथ निगरानी और गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। केवल ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाकर विभाग खुद पाक-साफ नहीं बन सकता।

यह मामला अपवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि सबक बनना चाहिए। हर बड़े निर्माण की स्वतंत्र गुणवत्ता जांच, जवाबदेही और गारंटी अधिध में ठेकेदार से अनिवार्य मरम्मत सुनिश्चित हो। जनता के पैसे से घटिया काम और फिर जनता के पैसे से उसकी मरम्मत – यह व्यवस्था अब नहीं चलनी चाहिए। मध्यप्रदेश में लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली पूरे विश्व में प्रख्यात है। फलाई ओवर अभी निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है, परंतु विभाग की एजेंसी पर मेहरवानी आश्चर्य का विषय।

वजन घटाने की होड़ में सेहत से खिलवाड़, रेटाट्राइड के नाम पर नया जल

वजन घटाने की चाह ने एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। मोटापे से जूझ रहे लोग सुनी-सुनाई बातों और इंटरनेट मीडिया पर फर्जी प्रचार को देखकर दवाएं मांग रहे हैं और जान जोखिम में डालकर इनका सेवन कर रहे हैं। यह हाल कुछ देशों में तेजी से उभर रहे एक खतरनाक ट्रेंड का है। रेटाट्राइड नाम की जिस दवा को वजन घटाने के क्षेत्र में संभावित बिक्रमयावबी के तौर पर देखा जा रहा है, उसकी असली दवा अभी बाजार में उपलब्ध भी नहीं है। इसके बावजूद इसके नाम पर नकली और गैरकानूनी उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट मीडिया, जिम और ब्यूटी सैलून से लेकर ब्लैक मार्केट तक में इसकी चर्चा है।

रेटाट्राइड को लेकर शोर इसलिए भी है कि लोग इसे वजन घटाने के आसान रास्ते के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन नकली इंजेक्शन में क्या है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गलत डोज से गंभीर साइड इफेक्ट का खतरा रहता है। वजन घटाने की चाह में सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक नकली उत्पादों के इस्तेमाल के बाद उल्टी, दस्त और बेचैनी जैसी

नईदुनिया

जानापाव से महाकाल तक आस्था का नया कॉरिडोर

जब विकास की बात होती है तो अक्सर सड़क, बिजली और उद्योग की चर्चा होती है, लेकिन मध्यप्रदेश में अब विकास की परिभाषा बदल रही है। यहां आस्था को भी विकास के केंद्र में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा जानापाव में 17 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन इसी नई सोच का प्रतीक है। श्रीकृष्ण-परशुराम लोक महाकाल लोक की तर्ज पर आकार लेगा और यह केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सनातन परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रयास है।

जानापाव कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यह वह भूमि है, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की और सुदर्शन चक्र हासिल किया। यही वह स्थान है, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है और जहां से साढ़े सात नदियों का उद्गम होता है। ऐसे में इसका विकास केवल पर्यटन विकास नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ऋण चुकाने जैसा है। पांच हजार वर्ष पुराना संबंध जब आज के विकास से जुड़ता है तो उसकी गूंज दूर तक जाती है।

इस परियोजना में करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से कई कार्य भ्रस्तावित हैं। इसमें भव्य ऑडिटोरियम, ध्यान कुटीर, हर्बल गार्डन, लैंडस्केपिंग, बहुउद्देशीय भवन और जनसुविधाओं का विकास शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रोपवे का है। जानापाव की पहाड़ी तक पहुंचना बुजुर्गों और बच्चों के लिए कठिन है। रोपवे बनने से यह बाधा दूर होगी और श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ेगी।

मध्यप्रदेश का भगवान श्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम से गहरा नाता है। प्रदेश में जहां-जहां उनके चरण पड़े, उन स्थलों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। चित्रकूट, श्रीराम के वनगमन

हिमालय की सफेद चादर पर काले धब्बे का खतरा

हिमालय के ग्लेशियरों पर अब सिर्फ बढ़ते तापमान का खतरा नहीं है। हवा में मौजूद कालिख और धूल भी बर्फ के पिघलने की रफ्तार बढ़ा रही है। गाड़ियों, कोयला बिजलीघरों, फैक्ट्रियों, ईंट भट्टों, घरों के चूल्हों और जंगलों व खेतों में लगने वाली आग से निकलने वाले कण हवा के साथ ऊंचे पहाड़ों तक पहुंचते हैं और ग्लेशियरों की सफेद स्तह पर जम जाते हैं। बर्फ पर जमी कालिख सूरज की गर्मी ज्यादा सोखती है। इससे बर्फ जल्दी पिघलने लगती है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों की चिंता इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के साथ प्रदूषण का यह असर ग्लेशियरों को कमजोर और अस्थिर कर सकता है।

सफेद बर्फ सूज की रोशनी को वापस लौटा देती है। इसे विज्ञान में अल्बेडो प्रभाव कहा जाता है। लेकिन जब बर्फ पर काली धूल जम जाती है तो वही बर्फ काली सतह की तरह गर्मी सोखने लगती है। एक छोटा सा काला कण अपने आसपास की कई गुना बर्फ पिघला सकता है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे पूरे ग्लेशियर को अंदर से खोखला कर सकती है। यह प्रदूषण केवल हिमालय के आसपास का नहीं है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जलने वाली पराली का धुआं, दिल्ली जैसे शहरों का वाहन प्रदूषण और उत्तर प्रदेश-बिहार के ईंट भट्टों की कालिख हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर करके हिमालय तक पहुंच सकती है। सर्दियों में जब हवा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर होता है तो यह प्रदूषण सीधे पहाड़ों पर जमा हो सकता है।

नेपाल इसका चिंताजनक उदाहरण है। यहां हाल में ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक बाढ़ आई और भारी नुकसान हुआ। इस घटना की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बढ़ता तापमान और ग्लेशियरों पर जमा प्रदूषण ऐसे हादसों का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

नेपाल में आई यह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना बताती



से जुड़े आश्रम, रुक्मिणी हरण और धार जिले में हुए युद्ध से जुड़े स्थानों का इतिहास भी सामने लाने की तैयारी है। सरकार टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र सफिट के रूप में धार्मिक पर्यटन को देख रही है।

महाकाल लोक के बाद उज्जैन में जो परिवर्तन आया, वह किसी से छिपा नहीं है। वहां लाखों श्रद्धालु हर महीने आ रहे हैं। स्थानीय व्यापार, रोजगार और होटल उद्योग को नई गति मिली है। इसी मॉडल को अब जानापाव में दोहराने की योजना है। अगर यह सफल होता है तो मालवा-निमाड़ अंचल में धार्मिक पर्यटन का एक पूरा कॉरिडोर बन जाएगा, जो इंदौर,



उज्जैन, ऑकारेश्वर और जानापाव को एक साथ जोड़ेगा। जानापाव के आसपास आदिवासी और ग्रामीण आबादी रहती है। अब तक यहां केवल एक छोटा मंदिर और कुंड ही आकर्षण थे, लेकिन नई परियोजना के बाद यहां दुकानें बढ़ेंगी, गाइड का काम मिलेगा और परिवहन व भोजन की व्यवस्था से रोजगार पैदा होगा। आध्यात्मिक चेतना के साथ-साथ आर्थिक चेतना भी जागेगी। यही विकास का सच्चा अर्थ है, जहां आस्था भी बचे और आजीविका भी बढ़े।

इस परियोजना का राजनीतिक संदेश भी साफ है। सरकार यह बताना चाहती है कि विकास केवल

बदला दुनिया का नक्शा, अब बराबर दिखेगा हर देश का आकार

स्कूल

मैं विश्व के जिस मानचित्र को देखकर हम महाद्वीपों और देशों का आकार समझते रहे, वह दुनिया की सही तस्वीर नहीं है। अब इस भौगोलिक भ्रम को सुधारने की कोशिश शुरू हो गई है। शुक्रवार को महासभा यूएनजीए ने एक प्रस्ताव को भारत सहित 164 देशों के समर्थन से मंजूरी दे दी है। अमेरिका अकेला देश रहा, जिसने विरोध में मतदान किया, जबकि छह देशों ने मतदान से दूरी बनाई। फ्रांस ने समर्थन के साथ यह भी कहा कि नक्शा बदलने के बाद भी दुनिया नहीं बदलेगी।

संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव के अनुसार अब दुनिया को एक नए मानचित्र से देखा जाएगा, जिसका नाम है इक्वल अर्थ मानचित्र। यह मानचित्र जापानी वास्तुकार हाजीमे नाकामुरा और अमेरिकी भूगोलवेत्ता योजन साविक द्वारा विकसित किया गया है। यह नक्शा दुनिया के देशों को उनके वास्तविक आकार के अनुपात में दिखाता है। अब तक जो नक्शा हम देखते आ रहे थे, वह 1569 में बने मर्केटर प्रोजेक्शन पर आधारित था, जिसने दुनिया को गलत अनुपात में दिखाया।

मर्केटर प्रोजेक्शन को 1569 में समुद्री यात्राओं के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य दिशा निर्धारण में मदद करना था, लेकिन इस नक्शे में भूभूध्न रेखा से दूर स्थित देशों को बहुत बड़ा दिखाया गया, जबकि अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे देशों को छोटा कर दिया गया। उदाहरण के लिए, ग्रीनलैंड को अफ्रीका के बराबर दिखाया जाता है, जबकि असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से दक्षिण लगभग पांच गुना बड़ा है। इस नक्शे ने अनजाने में एक मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता का भाव पैदा किया, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका बड़े और शक्तिशाली लगते थे, जबकि अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका छोटे दिखाई देते थे। प्रचलित नक्शे में वास्तविक आकार से कितना बड़ा दिखता है, इसके आंकड़े चौंकाते हैं। ग्रीनलैंड 73.9 प्रतिशत बड़ा, रूस 53 प्रतिशत, कनाडा 47 प्रतिशत, ब्रिटेन 41.1 प्रतिशत, अमेरिका 40 से 50 प्रतिशत, स्पेन 23.7 प्रतिशत, तुर्की 22.2 प्रतिशत, चीन 20.2 प्रतिशत,



अफगानिस्तान 16.8 प्रतिशत, अर्जेंटीना 18.2 प्रतिशत, ईरान 15.6 प्रतिशत, मेक्सिको 8.6 प्रतिशत, भारत 8 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका 12.4 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया 10 प्रतिशत और ब्राजील 2.3 प्रतिशत बड़ा दिखता है। इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तरी देशों को जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाया गया है। मानचित्र का इतिहास मिट्टी की पट्टिका से डिजिटल ग्लोब तक बहुत लंबा रहा है। पांचवीं सदी ईसा पूर्व में यूनानी विद्वानों ने पृथ्वी और ज्ञात दुनिया के नक्शे का वैज्ञानिक मानचित्रण शुरू किया। दूसरी सदी में टॉलेमी ने गणितीय मानचित्रण को आधार दिया। 1154 में अल-इदरीसी ने मध्ययुगीन दुनिया का मानचित्र बनाया। 1569 में समुद्री यात्राओं के लिए मर्केटर प्रोजेक्शन बनाया गया, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। बीसवीं सदी में हवाई तस्वीरों और सैटेलाइट ने नक्शे को अधिक सटीक बनाया। आज डिजिटल युग में सैटेलाइट और जीपीएस से दुनिया का सटीक नक्शा बन रहा है। नए मानचित्र में एक सच्चाई और उजागर हुई है। अफ्रीका महाद्वीप का आकार इतना बड़ा है कि इसमें अमेरिका, चीन, भारत, जापान, मैक्सिको और अधिकांश यूरोप समा सकते हैं, फिर भी जगह बचेगी।

मौजूदा मानचित्र में अलास्का ब्राजील के बराबर दिखता है, जबकि असल में ब्राजील लगभग पांच गुना बड़ा है। अलास्का 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जबकि ब्राजील लगभग 85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अंतर अब नए नक्शे में साफ दिखेगा। भारत सहित 164 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि यह नक्शा विकासशील देशों के साथ न्याय करता है। लिथुआनिया, मोल्दोवा

और यूक्रेन जैसे देशों ने भी समर्थन किया है, जो अक्सर नक्शे पर छोटे दिखते हैं। फ्रांस ने समर्थन करते हुए कहा कि नक्शा बदलने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन सोच बदलती है। अमेरिका ने इसका विरोध किया है, क्योंकि प्रचलित नक्शा पश्चिमी प्रभुत्व की भावना को मजबूत करता है। नक्शा केवल कामज का टुकड़ा नहीं है, यह सोच को बनाता है। जब एक बच्चा स्कूल में देखता है कि उसका देश छोटा है और यूरोप बड़ा है तो उसके मन में हीन भावना आती है। इक्वल अर्थ मानचित्र इस हीन भावना को खत्म करेगा। यह बताएगा कि अफ्रीका छोटा नहीं, बल्कि विशाल है। भारत छोटा नहीं, बल्कि उपमहाद्वीप है। दक्षिणी देश भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितने उत्तरी देश। यह नक्शा बराबरी का संदेश देता है।

अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, स्कूल और सरकारी कार्यालय नए नक्शे के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे। धीरे-धीरे पुराने मर्केटर प्रोजेक्शन की जगह इक्वल अर्थ लेगा। हालांकि यह बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग 457 साल से एक ही नक्शे को देखते आ रहे हैं। लेकिन बदलाव जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी दुनिया को सही नजर से देख सके। नक्शा बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा। 457 साल बाद दुनिया का नक्शा बदल रहा है। यह केवल भूगोल का सुधार नहीं, बल्कि इतिहास की एक भूल का सुधार है। जब हर देश को उसके वास्तविक आकार में दिखाया जाएगा तो दुनिया ज्यादा न्यायपूर्ण दिखेगी। भारत जैसे देशों के लिए यह गांव का विषय है कि उन्होंने इस बदलाव का समर्थन किया है। यह नया नक्शा केवल कामज पर लकीरें नहीं, बल्कि बराबरी का प्रतीक है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)



मंगाकर खुद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं। कई यूजर इंटरनेट पर इसके इस्तेमाल से वजन कम होने के अनुभव और पहले की तस्वीरें भी

साझा कर रहे हैं। प्रायोजित ट्रायल के बाहर रेटाट्राइड होने का दावा करने वाला कोई उत्पाद असली नहीं है। विज्ञापनों और इंटरनेट मीडिया

नहीं है। ऐसे में नकली इंजेक्शन लगाना मौत को दावत देना है। जब दवा बाजार में है ही नहीं तो इसके नाम पर उत्पाद कैसे बिक रहे हैं? इसका उत्तर कमजोर निगरानी और सख्त कानून की कमी में छिपा है।

ब्लैक मार्केट में नकली दवाओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त कार्रवाई करे और लोगों को जागरूक करे। वजन घटाने की होड़ में सेहत से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। किसी भी दवा या इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों के झंझसे में न आएँ। याद रखिए, पतला दिखने से ज्यादा जरूरी है स्वस्थ रहना। शॉर्टकट से मिलने वाली खूबसूरती लंबे समय में बीमारी बन सकती है। वजन घटाने की चाह में बाजार में आए नए जाल से बचना होगा। रेटाट्राइड के नाम पर बिक रहा हर उत्पाद खतरनाक हो सकता है। सरकार, चिकित्सक और समाज सभी को मिलकर इस भ्रम को तोड़ना होगा, तभी लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)